सौराष्ट्र-कच्छ क्षेत्र में ड्रिप सिंचाई

*245. **श्री चिमनभाई हरिभाई शुक्ल:** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आज की तिथि के अनुसार सौराष्ट्र-कच्छ क्षेत्र, में विशेषकर राजकोट और जामनगर जिलों में ड्रिप-सिंचाई प्रणाली के अन्तर्गत कितना-कितना क्षेत्र लाया गया है;

(ख) सरकार द्वारा इस संबंध में अब तक क्या-क्या सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं; और

(ग) क्या सरकार ने इस संबंध में सौराष्ट्र-कच्छ क्षेत्र के लिए कोई समयबद्ध कार्यक्रम बनाया है?

कृषि मंत्री (श्री चतुरानन मिश्र): (क) 1991-92 से 1995-96 तक सौराष्ट्र और कच्छ क्षेत्र में ड्रिप सिंचाई पद्धति के अन्तर्गत 2982 हैक्टेयर क्षेत्र शामिल किया गया है। इसमें राजकोट जिले का 489 हैक्टेयर क्षेत्र और जामनगर जिले का 136 हैक्टेयर क्षेत्र भी शामिल है।

(ख) उपरोक्त अवधि के दौरान सौराष्ट्र और कच्छ क्षेत्र में ड्रिप सिंचाई पद्धति की लागत पर राजसहायता के रूप में 395.94 लाख रुपए दिए गए हैं। इसमें राजकोट तथा जामनगर के लिए क्रमशः 70.20 लाख रुपए और 17.97 लाख रुपए शामिल हैं।

(ग) जी, नहीं।

वायु और जल (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम के अंतर्गत दर्ज किए गए मामले

246. **श्री ईश दत्त यादव:**
श्री कनकसिंह मोहनसिंह मंगरोला:

क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत दो वर्षों के दौरान वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम और जल (प्रदूषण और नियंत्रण) अधिनियम के अंतर्गत वर्षवार कितने-कितने मामले दर्ज किए गए हैं, और

(ख) कितने-कितने मामलों में न्यायालयों द्वारा प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों के पक्ष में अथवा उनके विरुद्ध निर्णय दिया गया है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन जय नारायण प्रसाद निषाद): (क) और (ख) पिछले दो वर्षों के दौरान वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 और जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 के तहत दायर किए गए मामलों की संख्या और न्यायालय द्वारा प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों के पक्ष में अथवा उनके विरुद्ध निर्णीत मामलों की संख्या नीचे सारणी में दी गई है:

वर्ष	दायर किए गए मामलों की संख्या			वायु अधिनियम के तहत निर्णीत मामलों की संख्या		जल अधिनियम के तहत निर्णीत मामलों की संख्या		पक्ष में (5+7)	कुल विरुद्ध (6×8)
	वायुअधि०	जल अधि०	कुल	बोर्ड के पक्ष में	बोर्ड के विरुद्ध	बोर्ड के पक्ष में	बोर्ड के विरुद्ध		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
1994-95	23	238	261	21	51	86	182	107	233
1995-96	25	246	271	6	13	22	64	28	77

ऊपर सारणी में दी गई निर्णीत मामलों की संख्या में उन मामलों के निर्णय भी सम्मिलित हैं जो 31.3.94 से पहले प्रारंभ किए गए थे।